



सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या—cm-255
09/06/2017

हर घर तक विकास की रोशनी पहुँचे, सभी का
विकास हो :- मुख्यमंत्री

पटना, 09 जून 2017 :- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज ग्राम मोबारकपुर नालंदा में आयोजित युवा एवं किसान जदयू का एकदिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुये कहा कि बहुत दिन बाद इस गाँव में आकर मुझे काफी खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि विधायक एवं सांसद के रूप में हम निरंतर क्षेत्र घूमते रहते थे। सप्ताह में दो दिन क्षेत्र भ्रमण के लिये समर्पित था। केन्द्र में मंत्री थे, तब भी चले आते थे। उस वक्त घूमने में काफी तकलिफ होती थी। रास्ता टूटा हुआ था, हम ज्यादा पैदल ही चलते रहते थे। उन्होंने कहा कि पिछले 10-11 साल से बिहार के लोगों ने जो जिम्मेवारी सौंपी है, उसे निभाने में लगा रहता हूँ। अब भ्रमण का उतना समय नहीं मिल पाता है, इससे मुझे भीतर से पीड़ा होती है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मेरे पुराने साथी आये थे, मुझे मोबारकपुर आने को कहा। मैंने पूछा कि पहले कोई काम है तो बता दीजिये। मैंने सभी जगहों से जानकारी प्राप्त की, उस पर सभी से बात किया। यहाँ के सभी सड़क को ठीक करने के साथ-साथ सिंचाई के लिये भी पहले ही निर्देश दे चुका था। मनरेगा से भी काफी काम हुआ है। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक राज्य में एक भी बसावट नहीं बचेगा, जहाँ बिजली नहीं पहुँचा दिया जायेगा। साथ ही अगले साल के अंत तक कोई घर नहीं बचेगा, जहाँ से बिजली पहुँचा नहीं दी गयी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा विकास के लिये पूर्व से चलायी जा रही सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ सात निश्चय योजना को अपनाया गया। सात निश्चय को महागठबंधन के साझा कार्यक्रम में स्वीकार किया गया। चुनाव के बाद सरकार बनी। सात निश्चय की योजनाओं को मंजूरी दी गयी, इसके क्रियान्वयन के लिये विभिन्न योजनाओं का सूत्रण किया गया। आज सभी पर काम चल रहा है। इन्हीं सात निश्चय योजना में से एक निश्चय हर घर बिजली का कनेक्शन है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय में से एक निश्चय महिलाओं को सभी प्रकार की सरकारी सेवा में 35 प्रतिशत आरक्षण देने का है। उन्होंने कहा कि बिहार पहला राज्य है, जिसने पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकाय चुनावों में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण दिया है। बिहार में महिलाओं को पहले ही पुलिस की नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि महिलाओं के लिये सभी सरकारी सेवाओं में 35 प्रतिशत आरक्षण देने के निश्चय को जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय योजनान्तर्गत एक निश्चय योजना हर घर नल का जल है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुआँ एवं चापाकल भी रहेंगे। उसके अलावा हर घर में नल का जल उपलब्ध कराया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ-साथ सात निश्चय में से एक निश्चय हर घर तक पक्की गली एवं नाली का निर्माण है। उन्होंने कहा कि गाँव के बाहर सड़क तो बन जाती है, पर गाँव के अंदर स्थिति ठीक नहीं रहती है। लोगों के मन में इसके लिये ख्वाहिश रहती है इसलिये हमने तय किया है कि सभी गलियों का पक्कीकरण किया जायेगा ताकि लोगों को कीचड़ पर से गुजरना न पड़े। उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन विकेंद्रित तरीके से किया जा रहा है। पंचायतों एवं नगर

निकायों के माध्यम से काम कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चार साल के अंदर कार्य को पूरा करना है इसलिये वार्डवार इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वार्डों में पहले उन वार्डों को लिया जायेगा, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति की बहुलता हो। उन्होंने कहा कि गाँव के लोगों की सबसे ज्यादा ख्वाहिश होती है कि उनके गाँव का नाली एवं सड़क पक्का रहे तथा शहरों की तरह उन्हें भी नल का जल उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि हमलोगों ने सभी की भावनाओं को देखते हुये इन योजनाओं का क्रियान्वयन करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में कुछ मतभेद था। कानून में संशोधन का अध्यादेश लाकर सभी को इसमें शामिल किया गया है। पंचायत स्तर पर लोक निर्माण समिति को और विस्तृत बना दिया गया है। वार्ड सदस्य भी इसके सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी ताकत ग्राम सभा एवं उसी तरह वार्ड सभा है। उन्होंने कहा कि कितना बड़ा काम हो रहा है। पैसा जनता का है, उसे खर्च करने के लिये नियम एवं तरीका होता है। हम ठेकेदारों के द्वारा नहीं बल्कि ग्राम पंचायत और जन सहयोग के द्वारा कार्य कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पहले पेयजल योजनान्तर्गत जलमीनार का निर्माण किया जाता था। किसी भी पेयजल योजना के कुल राशि का 35-40 प्रतिशत जलमीनार के निर्माण पर खर्च होता है। उन्होंने कहा कि शहर के लिये जलमीनार ठीक है परंतु गाँव में उसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि सब कुछ सौच-विचार कर वार्ड के आधार पर काम किया जा रहा है, इसमें सभी की भूमिका है, इसमें सभी लोगों की पूर्ण सहभागिता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम न्याय के साथ विकास में विश्वास रखते हैं। विकास का फायदा जन-जन तक पहुँचे। उन्होंने कहा कि हर घर तक विकास की रोशनी पहुँचे, सभी का विकास हो, यही मेरा उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि सात निश्चय में से एक और निश्चय हर घर में शौचालय का निर्माण है। उन्होंने कहा कि अगर खुले में शौच से मुक्ति तथा पीने के लिये शुद्ध पेयजल मिल जाय तो नब्बे प्रतिशत बीमारियों से छुटकारा मिल जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिये काफी काम किया गया है। बिहार में संस्थानों की कमी है। इसे देखते हुये हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, महिला आईटीआई, सभी अनुमण्डलों में आईटीआई, एनएमएल कॉलेज, सभी जिलों में जीनएम कॉलेज, पाँच नये मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। इन सभी पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 12वीं से आगे पढ़ने वाले छात्रों की संख्या मात्र 13.9 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि जब तक उच्च शिक्षा में युवा नहीं जायेंगे, तब तक विकास का सपना साकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य कारण गरीबी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले गरीबी के कारण माँ-बाप लड़कियों को प्राइमरी स्कूल के आगे नहीं पढ़ाते थे। इसको देखते हुये पोशाक योजना एवं साइकिल योजना की शुरुआत की गयी। जहाँ पहले वर्ग 9 में पढ़ रही लड़कियों की संख्या एक लाख 70 हजार थी, वह अब बढ़कर नौ लाख हो गयी है। उन्होंने कहा कि 12वीं के आगे पढ़ने वाले इच्छुक छात्र-छात्राओं के लिये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजनान्तर्गत छात्र-छात्राओं को चार लाख रुपये तक की राशि उपलब्ध करायी जायेगी। राशि पर पूर्ण गारंटी राज्य सरकार गारंटी देती है। मूलधन ही नहीं सूद दोनों पर सरकार की गारंटी है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा वैसे 20 से 25 साल के युवा जो रोजगार तलाश रहे हैं, उन्हें दो वर्षों तक एक हजार रुपये का स्वयं सहायता भता उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि बाहर रोजगार तलाशने वाले युवाओं के लिये कम्प्यूटर का ज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी बोलने के साथ-साथ व्यवहार की कुशलता होनी चाहिये। ऐसे युवाओं के लिये कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत की गयी है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा उद्यमी युवाओं के लिये वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिये सभी सरकारी

महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। अब तक तीन सौ संस्थानों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है। उन्होंने कहा कि आप इस सुविधा का उपयोग ज्ञान अर्जन के लिये कीजियेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में शराबबंदी का कार्य हुआ है। 9 जुलाई 2015 को महिलाओं के एक कार्यक्रम में भाषण देकर जैसे ही मैं बैठा था कि पीछे से आवाज आयी कि शराबबंदी कीजिये। मैंने पुनः माइक पर आकर कहा कि अगली बार सता में आऊँगा तो शराबबंदी लागू करूँगा। आपने पुनः दोबारा काम करने का मौका दिया। सरकार बनी और 26 नवम्बर 2015 को यह एलान किया गया कि 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू किया जायेगा। 1 अप्रैल 2016 से ग्रामीण क्षेत्रों में तथा चार दिन बाद 5 अप्रैल 2016 से शहरी क्षेत्रों में भी पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गयी। शराबबंदी के बाद आज कितना परिवर्तन आया है। लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा शराब में गंवा देते थे। आज वही पैसा परिवार के विकास के लिये खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम घूमते रहते हैं। इसी भ्रमण के क्रम में एक जगह महिला द्वारा बताया गया कि पहले पति शराब पीकर घर आते थे, झगड़ा झंझट करते थे, देखने में क्रूर लगते थे। अब शराबबंदी के बाद शाम को हंसते हुये आते हैं, साथ में सब्जी लेकर आते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। उन्होंने कहा कि इसी को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। नारी को घरेलू हिंसा से छुटकारा मिला। कुछ लोग इधर-उधर छिटपुट कुछ कार्य करते रहते हैं। उन पर नजर रखी जा रही है। जो भी पकड़ा जायेगा, कड़ी कार्रवाई होगी। शराबबंदी से कोई समझौता नहीं होगा। अब हम शराबबंदी से नशामुक्ति की ओर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि आप सभी को ध्यान रखना है कि शराब छोड़कर कोई दूसरा मादक पदार्थ का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी एवं नशामुक्ति के पक्ष में 21 जनवरी 2017 को मानव श्रृंखला बनायी गयी थी। मानव श्रृंखला में चार करोड़ लोग शामिल हुये थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आगे समाज सुधार के अन्य विषयों पर भी अभियान चलायेंगे। इनमें बाल विवाह है। बाल विवाह तो कानूनी तौर पर वर्जित है परंतु फिर भी बाल विवाह देखा जाता है। उन्होंने कहा कि शादी के समय लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिये। अगर लड़की की शादी कम उम्र में होती है और वह गर्भ धारण करती है तो बच्चे का विकास सही नहीं होता तथा शिशु को काफी कठिनाई होती है। स्टटिंग ग्रोथ का उदाहरण देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिये कुपोषण मुख्यतः जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि सभी स्वयं सहायता समूह की दीदी, आशा कार्यकर्ता, आँगनबाड़ी सेविका, सहायिका, शिक्षक-शिक्षिकायें, समाजसेवी, राजनीतिक कार्यकर्ता सभी से अनुरोध करता हूँ कि वे घर-घर जाकर इन बातों को बतायें और लोगों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि दूसरा है दहेज प्रथा। पहले संपन्न लोगों के बीच दहेज प्रथा देखा जाता था परंतु अब यह प्रवृत्ति समाज के सभी वर्गों में देखी जाती है। यह एक विनाशकारी प्रवृत्ति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गाँधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर से इन दोनों यथा-बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के खिलाफ सशक्त अभियान चलाया जायेगा। आपलोग इसके लिये तैयार हो जायें। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि अगर किसी शादी में दहेज लिया जा रहा है तो उसमें शामिल नहीं हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदैव सचेत और सक्रिय रहियेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहारियों के बल पर बिहार आगे बढ़ रहा है। बाहर की सहायता से नहीं हमारे लोग मेहनती हैं, हमारी युवा प्रतिभाशाली है। देश में कहीं भी किसी प्रकार की परीक्षा हो, बिहार के छात्र ही उत्तीर्ण होते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में किसानों की हालत अच्छी नहीं है। हमने किसानों के लिये कृषि रोड मैप बनाया है। हमारा लक्ष्य है कि किसानों की आमदनी बढ़े। उन्होंने कहा कि मैं अपनी क्षमता भर आपलोगों की सेवा करता

रहूँगा। जब तक जिन्दा हूँ, तब तक आपकी सेवा करता रहूँगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्कर्मित मध्य विद्यालय शादिकपुर को उत्कर्मित कर उच्च विद्यालय बनाने की घोषणा की। साथ ही शादिकपुर में स्वास्थ्य उप केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री को कार्यकर्ताओं द्वारा फूलों का बड़ा माला पहनाया गया। साथ ही मुख्यमंत्री को अंगवस्त्र एवं सम्मान पत्र भेंट किया गया। इस अवसर पर उत्कर्मित मध्य विद्यालय शादिकपुर में मुख्यमंत्री द्वारा वृक्षारोपण किया गया।

इस अवसर पर नालंदा जिला के प्रभारी मंत्री श्री शैलेश कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार, सांसद श्री कौशलेन्द्र कुमार, विधायक श्री चन्द्रसेन प्रसाद, विधायक श्री जीतेन्द्र कुमार, विधान पार्षद श्री संजय कुमार सिंह उर्फ गाँधीजी, विधान पार्षद श्री हीरा प्रसाद बिन्द, विधान पार्षद श्रीमती रीना यादव सहित अन्य राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
